Steps to encourage quality control of Garments

*164. SHRI SOM PAL:f

SHRI ANANTRAY DEV-
SHANKER DAVE:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Japan Apparel Manufacturers Association has complained regarding the delay and poor quality of Indian garment exports;

(b) if- so, what are the details thereof;

(c) whether compaintg are coming from other countries also;

(d) if so, what are the details thereof; and

(e) what is being done to encourage quality control?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) Neither the Government nor the Apparel Export Promotion Council has received any complaint from the Japan Apparel Manufacturers Association or any other country regarding delay in delivery or poor quality of Indian garment exports.

(e) In recent months Government have taken a number of measures to help the garment exporters to attain internationally accepted standards of quality for their products like facilitating import of new textile and garment machinery, introduction of liberalised Export Promotion (Capital Goods) Scheme, easier access to raw material of international quality, enabling import of second hand garment machinery, inculcating quality conciousness among exporters etc.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Som Pal.

SHRI SOM PAL: The statement says that the Government or the AEPC has not received any complaint on this account from the Japan Apparel Manufacturers Association, but I myself have seen certain write. ups in the newspapers, in 'Economic Times' and other important papers of India that there is a complaint from the Association of Japanese importers in this regard. The question is that the apparatus which monitors our exports, which have a big scope in international market because of their major labour content, seems to be poor. It is a question of sensitising our apparatus that monitors these things. According to my information a major problem faced by *the* apparel exporters is that the quality of man-made fibre and its aavilatiility is not up to the standard. The quantity required is also not available. What is the Ministry thinking of doing in this regard to improve the availability of internationally accepted standards of man-made fibres so that they catch up with the other exporters and we do not lose market in the long run?

श्री अशोक गहलोत : उपसभापति महोदया, जहां तक शिकायत की बात की गई है मैं अपने उत्तर में कह चुका हूं कि ऐसी कोई शिकायत न सरकार को मिली है और न ही ए०ई०पी०सी० को मिली है हमने जापान में भी एम्बेसी के माध्यम से पता करवाया था तो यह मालूम पड़ा कि जिसको कोट किया गया है तथा जिस न्यूज का हमारे माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं, उनका कहना है कि मैंने जनरल रिमार्क्स सेमीनार में किया था सिर्फ भारत के लिए नहीं किया था। यह हमारी इफार्मेशन है । इसके अलावा कोई और इफार्मेशन माननीय सदस्य देंगे तो उस शिकायत को भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे ।

जहां तक क्वालिटी की बात है, जिस प्रकार से जापान के अंदर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है,, मैं समझता हू कि क्वालिटी में इम्प्रूव करने की गुंजाइश आज भी मौजूद है । इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और हमारी कोशिश रहती है कि हम क्वालिटी को इम्प्रूव करा सकें जिससे कि और अधिक हमारा एक्सपोर्ट बढ़े । जो एक्सपोर्ट हुआ है उसकी फिगर्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हमारी क्वालिटी है उसको भी वह लोग पसंद करते है और बायर्स-सेलर्स का जो एग्रीमेंट होता है उसके आधार पर एक्सपोर्ट होता है । मैं समझता हूं कि उससे हमें संतुष्टि प्रगट करनी चाहिए ।

SHRI SOM PAL: But you have not said anything about the availability and the quality of the man-made fibre.

THE DEPUTY CHAIRMAN: This is your second supplementary.

SHRI SOM PAL: No, Madam, this is a part of my first supplementary.

श्री अशोक गहलोत : जब भी ऐसी शिकायतें आती हैं, हम दूर करने की कोशिश करते हैं ।

उपसभापति : सैकिंड सप्लीमेंट्री है या खत्म हो गयी ?

श्री सोमपाल : है, दूसरी । हिन्दी में पूछता हूं क्योंकि मेरे बी०जे०पी० के सदस्य कह रहे हैं ।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : वह संस्कृत में भी बोल सकते हैं ।

श्री सोमपाल : महोदया, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न वस्त्रों के निर्यात के सम्बन्ध में है, सूती वस्त्रों से सम्बन्धित है । मेरी सूचना के अनुसार सूती वस्त्रों की किस्में ऐसी हैं खास तौर से भारी किस्में, जिन्हें डाक्टर्स यूनिफार्म में हास्पिटल में पहनकर जाते हैं, वे किस्में यहां उपलब्ध नहीं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट और उनके मानक के समकक्ष हो । उसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार क्या करने जा रही है क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा स्कोप इटरनेशनल मार्केट में है ?

श्री अशोक गहलोत : ऐसी कोई इफार्मेशन हमारे पास नहीं रहती है । उसके बावजूद भी जो ध्यान माननीय सदस्य ने आकर्षित किया है, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसका एक्सपोर्ट भी ज्यादा हो सके ।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : उपसभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहूगा कि 1977 में कौल कमेटी गठित की गई थी । कांडला फ्री ट्रेड जोन, जो 100 परसेंट एक्सपोर्ट जोन है, उस समिति ने कई सिफारिशें की थीं । आज तक वह जोन, अलग-अलग मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस या उनके सरकुलर पर चल रहा है । उसमें एक जो सिफारिश है, वह यह है कि जोन के लिए कोई कानून बनना चाहिए । मैडम, जो डिले हो रहा है, डिले इसलिए हो रहा है कि आज के दिन तक वहां कोई कानून नहीं है । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूगा कि क्या सरकार इस जोन के लिएकोई कानून बनाकर, जो डिले हो रही है, व डिले न हो क्योंकि वैरियस मिनिस्ट्रीज के गाइडलाइंस और सकुलर्स पर यह जोन चलता है । तो क्या सरकार यह सोचेगी कि कानून जल्दी से जल्दी बने ?

श्री अशोक गहलोत : उपसभापति जी, जो कानून बनाने की बात है, कानून बनाने को कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि कामर्स मिनिस्ट्री डील करती है । हम उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे और आपको इनफोर्मेशन भिजवाएंगे कि उनके सामने क्या दिक्कत आ रही हैं ।

उपसभापति : डा० जे० के० जैन डाक्टरों की यूनिफार्म का तो पूछ लिया सवाल, अब आप क्या पूछेंगे नर्सों की यूनिफार्म पर ?

डा. जिनेन्द्र कुमार जैन : मैडम, विश्व के अनेक राष्ट्रों में भारतीय परिधान के निर्यात का मार्केट है लेकिन उन लोगों ने अपने-अपने देशों में भारतीय परिधानों के निर्यात के लिए कोटे निर्धारित किए हैं

उसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्टर है, वह जितना बेच सकता है, उतना नहीं कर पा रहा एक ओर तो भारतीय सरकार डंकल प्रपोजल्स को मानने के लिए बाहर के मार्केट में विश्व के अनेक राष्ट्रों को आने दे रही है, दूसरी ओर डंकल प्रपोजल्स को नैगोशिएट करते समय "गैट" में भारतीय सरकार इस बारे में सफलता प्राप्त नहीं कर पाई कि भारत के निर्यात भी इन सब देशों के अंदर, मल्टी फाईबर एग्रीमेंट के अंदर जो हमारे निर्यात का उन्होंने कोटा बांधा है, उसको हमारे एक्सपोर्टर्स को मदद करें । तो ये जो डंकल प्रपोजल्स का यूनीलेट्रल प्रभाव हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है उसके लिए भारतीय परिधानों के निर्यात के लिए सरकार किस प्रकार से भारतीय एक्सपोर्टर्स को राहत देना चाहती है, उसका जवाब मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं ।

श्री अशोक गहलौत : उपसभापति महोदया, डंकल प्रपोजल्स के बारे में तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे मंत्रालय से संबंधित नहीं है पर जहां तक एम०एफ०ए० की बात माननीय सदस्य ने कही है, हमारी कोशिश रहती है और हम खुद चाहते हैं कि कोटा फिक्स न हो और फ्री ट्रेड हो जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके और जिन कंट्रीज ने कोटा लगा रखा है, उसको हम कोशिश करते हैं ही कैसे हटा सकें । अभी ये बात हो रही थी तो उन्होंने 17 महीने और उसका बढ़ा दिया है । हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े और मैं आपके माध्यम से सदन को यह कहना चाहूंगा कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में रिसेशनरी ट्रेंड होते के बावजूद भी हमारे एक्सपोर्ट काफी बढ़ा है मैं फिगर पहले भी दे चुका हू उसके अंदर और इस बार, और कहना चाहूगा कि दो महीने के अंदर जो अप्रैल और मई गए हैं, उसमें भी हमारा एक्सपोर्ट काफी एनकरेजिंग है और बढ़ रहा है ।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, the international market for cotton garments is expanding every flay because poeple are moving away from synthetics and are looking for cotton textiles. Therefore, the export of Indian cotton garments has a very good market. But the point is, the quality has to be ensured. If the quality is not there, we are going to lose that market, I would like to ask the Minister, in view of the fact that the Export Inspection Agency has been abolished as part of its liberalization programme, what is the mechanism that the Government has to ensure that sub-standard garments are not sent abroad and we don't miss our international market?

श्री अशोक गहलौत : उपसभापति महोदया, जहां तक इंस्पैक्शन एजेंसी को हटाने की बात हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे एक्सपोर्ट्स में भी क्वालिटी कांशेसनैस काफी बढ़ गई और ऐसी कोई शिकायत अब आ नहीं रही हैं, जिसके बारे में हम चिंता करें जहां तक एक्सपोर्ट की क्वालिटी को बढ़ाने की बात हैं, हमने मैजर्स काफी लिए हैं जिसमें मशीनरी के आयात को नैगेटिव लिस्ट से निकाला गया है, टैक्सटाइल और गारमेंट मशीनरी के आयात को उसका ड्यूटी कम की गई है, उसके लिए हम लोग आई०एस० 900 और बी०एस०आई० 14000 के मापदंड को निर्धारित करने के लिए वर्कशाप्स और सेमिनार वगैरह कर रहे हैं । इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं । आप चाहेंगे तो, लंबी लिस्ट है, मैं माननीय सदस्य को अलग से भिजवा दूंगा ।

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAX: Madam, credibility is an important factor in trade. So, maintenance of credibility is very essential. In order to maintan credibility, we have to keep up quality. I want to know from the Minister, so far as textile goods are concerned, when they are exported, whether there is any device for pre_shipment random quality-control checks and sometimes as to quantity also What are the devices?

श्री अशोक गहलौत : उपसभापति महोदया, मैं कह चुका हूं कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हमें कोई दिक्कत

नहीं आ रही है हमारे एक्सपोर्टस में क्वालिटी कांशेसनैस बढ़ चुका है, कोई शिकायत हमारे पास न सरकार के लेवल पर आई है न ऐ०ई०पी०सी० के लेवल पर आई है। इसलिए माननीय सदस्य को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्रडिबिलिटी की जहां तक बात है, वह हमारे ध्यान में है, हम हमेशा उसको बनाए रखेंगे ।

श्री सुशीलकुमार सम्भाजीराव शिन्दे : महोदया क्या मंत्री ये बताएंगे कि आजकल लैदर गारमेंट काफी तौर से बढ़ रहा है, बढ़ोतरी हो रही है लेकिन जो ये लैदर गारमेंट में लोग काम करते हैं, जो दलितवर्गी हैं, जिनकी टैनरी है, वह छोटे-छोटे लोग हैं और बड़ा आदमी उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है ...

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is *on* textiles.

श्री सुशीलकुमार सम्भाजीराव शिन्दे : लैदर गारमेंट का भी इसमें आता है क्योंकि टुगेदर इनके सब लाइसेंसेज़ देते हैं । ये गारमेंट का क्वीश्चन है । तो इसलिए मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यदि दलितवर्गी डायरेक्टली उनसे डिपार्टमेंट से विनती करें तो उनको लाइसेंसेज़ या एक्सपोर्ट की परमीशन मिल जाएगी क्या ?

उपसभापति : कपड़े में तो बहुत सी चीजें आती है, तागा भी आता है, सुई भी आती है ।

श्री एन० के० पी० साल्वे : ये मेडन सवाल है मैडम... (व्यवधान) सवाल अच्छा है मिनिस्ट्री गलत है ?

श्री अशोक गहलौत : ये हमारे मंत्रालय से संबंधित नहीं है । मैं माननीय सदस्य को कामर्स मिनिस्ट्री से इनफारमेशन लेकर भिजवा दूंगा ।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय उपसभापति महोदया विकसित देशों में इन दिनों भारतीय परिधानों के पहनने की परंपरा बहुत जोरों पर है और खास करके काटन कपड़े की प्रक्रिया काफी तेजी से बढ़ रही है और एक बात मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि 1980 तक तो भारत का बाजार काफी जोरों पर था इन देशों में लेकिन 1980 के बाद हमारे कुछ प्रतिद्वंद्वी देश खास करके जो हमारे पड़ोसी देश थे, बंगला देश, श्रीलंका, इनका बाजार पर काफी जोर बढ़ा है और एक बात और मैं आप से कहना चाहूंगा कि पश्चिम के देशों में और जापान जैसे देशों में इसलिए इस तरह के कपड़ों की मांग बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारा मजदूर जो है वह काफी सस्ता है और वहां पर महंगाई काफी ज्यादा है इसलिए क्या मंत्री जी अपने एक्सपोर्ट के प्रमोशन में इस बात का ध्यान रख रहे हैं, कि श्रीलंका और बंगला देश का बाजार दुनिया के पाश्चात्य देशों के बाजार पर जो कब्जा कर रहा है, उस पर भारत को अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए किस तरह से आगे बढ़ना है वरना कुछ समय ऐसा जल्दी ही आपके सामने आने वाला है जहां आप दुनिया के इस बाजार से बाहर हट जाएंगे ।

श्री अशोक गहलौत : उपसभापति महोदया, माननीय सदस्य के अच्छे सुझाव हैं, हम उन पर ध्यान रखेंगे ।

*165. [*The questioner (Shri Mohammed Afzal* alias *Meem Afzal) was absent. For answer* vide *col.* 41 infra.]

*166. *[The questioner (Miss Saroj Khaparde') was* absent. *For answer* vide cols. 41-42 infra.]

SHRI S. JA1PAL REDDY: The Members are absent because they did not think that their turn would come.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: They thought that there will be no Question Hour due to Ayodhya. So,, they did not come.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Because of the encroachment if they are asking for the dismissal of the-U.P. Government,...

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, No, no. No comments on that. (Interruptions) .

DR. JINENDRA * KUMAR JAIN: The Bihar Government is going to answer. *(Interruptions)*

THE; DEPUTY CHAIRMAN; Please.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: The question relates to encroachment in Bihar. ... *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: No. Order... (Interruptions) Now no, please. No, please,

SHRIMATI KAMLA SINHA: Dr. Jain's aspersions should be expunged from the proceedings. These are absolutely irrelevant.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: These are very much relevant, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please, Dr Jain, no argument. Please sit down. .. (Interruptions)

DR JINENDRA KUMAR JAIN: The Member has asked the question. It is definitely relevant.

THE DEPUTY CHAIRMAN; Please take your seat,

I am happy that the Minister is present to answer the question. If the Member is not there, it is a different question.

Target for silk production

*167. SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN; Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) what is the target for production of silk for the year 1992-93; and

(b) what steps are being taken to achieve the target?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The silk production target for the year 1992-93 is 14,465 metric tonnes.

(b) A number of steps are being taken to achieve the production target like bringing additional area under mulberry, introduction of new varieties of mulberry, improving silk-worm seed quality development of new varieties of silkworm races, effective disease control measures etc,

SHRI TINDIVANAM G. VENKAT-RAMAN: In the answer given by the Minister, he has not stated the extent of the additional acreage or addition in acres, which is to boost up production. He has also not stated what are the new methods apart from the traditional methods of improving the seed quality and all that. What are the other steps which have been taken by his Ministry?

श्री अशोक गहलोत : उपसभापति जी, जो मूल प्रश्न में पूछा गया था मैंने उसका उत्तर दे दिया है और उसमें सब कुछ लिखा है । जो ट्रेडीशनल मेथड्स हैं वह काम में लिये जा रहे हैं इसके अलावा जो नेशनल सेरिकल प्रोजेक्ट चल रहा है उसके माध्यम से हमारी कोशिश है कि इन सारे ट्रेडीशनल मेथड्स को आगे बढ़ाया जाए और नान ट्रेडीशनल स्टेट्स में भी इस काम को आगे बढ़ाया जाए माननीय सदस्य को मालूम है कि नेशनल सेरिकल्च प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड बैंक की सहायता से चल रहा है काफी प्रगति पर है ।

SHRI TINDIVANAM G. VENKAT-RAMAN: I asked what has been the additional acreage...

THE DEPUTY CHAIRMAN: He said whatever are the traditional methods they are being used. Some new methods have been brought about with the support of the World Bank regarding the new varieties of silk worms and mulberry trees etc.

SHRI TINDIVANAM G. VENKAT-RAMAN: I want to know the additional acreage. He has not answered that.